महत्वपूर्ण एवं खास

दूल्हन के पिता से नोट से भरा बैग छीनकर भागा युवक, राजीव नगर की घटना

दुर्ग (आरएनएस)। दुल्हन के पिता लूट का शिकार हो गया। घटना 9 फरवरी की रात की है। अज्ञात युवक ने दुल्हन के पिता से 20 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। प्रार्थी हरिलाल साहू पटवा भवन में अपनी बेटी की शादी में मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। तभी एक युवक आया और हाथ में रखे बैग को लेकर भाग गया। बैग में कुल 20 हजार रुपये थे। समारोह स्थल में लूट की घटना होने के बाद सनसनी फैल गई। मेहमान एकत्रित हो गए। प्रार्थी के बेटों ने नोट से भरे बैग को लूटने वाले युवक का पीछा भी किया। लेकिन युवक राजीव नगर के किसी घर में जाकर छुप गया। प्रार्थी के बेटों ने युवकों को बहुत ढूंढने का प्रयास भी किया। लेकिन आरोपी युवक का कही पता नहीं चल पाया। प्रार्थी ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। अज्ञात युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

डोंगरगांव में तीन दिवसीय लोक मड़ई एवं कृषि मेला कल से

रायपुर (आरएनएस)। राजनांदगांव जिले के विकासखंड मुख्यालय डोंगरगांव में इस साल 15 फरवरी से 17 फरवरी तक लोक मड़ई एवं कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोक मड़ई के दौरान प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू लोक मड़ई एवं कृषि मेले के संरक्षक हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे 15 फरवरी की दोपहर 2 बजे लोक मड़ई एवं कृषि मेले का शुभारंभ करेंगे।

वैलेनटाइन डे पर माल्स एवं रेस्टोरेंट में पुलिस ने किये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम

» सुबह से ही युवाओं की टोली उत्साहपूर्वक मना रही हैं वैलेनटाइन डे

रायपुर (आरएनएस)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यूरोप के संत वैलेनटाइन का जन्मदिवस वैलेनटाइन डे के रूप में युवाओं द्वारा राजधानी सहित प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि संत वैलेनटाइन ने दुनिया को प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने का संदेश दिया था। उन्होंने आधी दुनिया में प्यार का संदेश प्रचारित व प्रसारित किया। उनकी स्मृति में आज युवाओं द्वारा वैलेनटाइन डे धूमधाम से मनाया जा रहा है।

प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा

रायपुर (आरएनएस)। राज्य के अधिकांश जिला पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने आसानी से जीत दर्ज कर ली है। राज्य के प्रमुख जिला पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। बात राजधानी रायपुर की करें तो यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार ने आसान जीत दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकांश जिला पंचायतों में अपनी आसान जीत दर्ज कर ली है। राजधानी रायपुर में जहां कांग्रेस की डोमेश्वरी वर्मा ने निर्णायक 12 मत प्राप्त किया तो वहीं भाजपा समर्थित ललिता वर्मा को केवल 4 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर दुर्ग में भी कांग्रेस की शालिनी वर्मा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। यहां उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस समर्थित अशोक साहू ने चुनाव जीता है।

कोरबा के सतरंगा में 23 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक निरस्त

रायपुर। कोरबा के सतरंगा में 23 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विभिन्न पदों का साक्षात्कार 29 फरवरी को

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री में असिस्टेंट रजिस्ट्रार (आईटी), कम्प्यूटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (आईटी), असिस्टेंट लाईब्रेरियन एवं लाईब्रेरी असिस्टेंट एजी-3 के पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 29 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, छतौनी रोड, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यापम रायपुर द्वारा उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर आरक्षण तालिका अनुसार साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने विकेन्द्रीकरण एक कारगर कदम

» प्रदेश में 704 नए ग्राम पंचायत और एक नए जिले का हुआ गठन

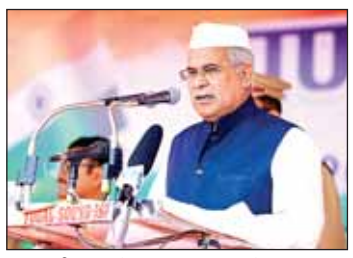

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों का विकेन्द्रीकरण जनहित में एक कारगर और सराहनीय कदम है।

प्रदेश के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण कर बड़ी पंचायतों का परिसीमन कर 704 नए पंचायतें गठित की गई है। जिनमें 496 नव गठित पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में है। इसे मिलाकर अब तक प्रदेश में 11 हजार 664 ग्राम पंचायतें हो गई है। बिलासपुर जिले का परिसीमन कर पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही नए जिला का गठन किया गया है। अब प्रदेश में 28 जिलें हो गए हैं। प्रदेश में 146 जनपद पंचायत, 150 तहसीलों के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के नागरिकों को मूलभूत सहित विभिन्न प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के शहरी, गरीबों, पिछड़ों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण लोगों के विकास के लिए दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज शहरी जीवन के साथ-साथ ग्रामीणों को भी प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही है, वहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जनभागीदारी पर विशेष प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 'छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, 1993' में संशोधन कर त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों की न्यूनतम् योग्यता मे कक्षा का मापदण्ड हटाकर 'साक्षर' कर दिया गया है। प्रदेश के 85 विकासखण्डों में पेसा कानून लागू है। राज्य सरकार इन अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत लोगों को पेसा कानून के अनुसार उनके अधिकार दिलाने और विकास को नई गति देने के लिए उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। पेसा कानून के तहत आने वाले इस क्षेत्र में यहां की परंपराओं, रीति-रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। बड़ी पंचायतों के परिसीमन से बनने वाले नवीन पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होगा।

चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद दर्जनों सिविल जजों का तबादला आदेश जारी

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के निर्देश पर सिविल जजों का थोक में तबादला आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल कार्यालय से जारी आदेश में सिविल न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी हो गया है।

श्रम न्यायाधीश राजनादगांव विवेक गर्ग को द्वितीय सिविल जज क्लास वन राजनादगांव, श्रम न्यायाधीश बिलासपुर गंगा पटेल को तृतीय सिविल जज क्लास वन बिलासपुर, श्रम न्यायाधीश अंबिकापुर दुलार सिंह को द्वितीय सिविल जज क्लास वन अंबिकापुर, श्रम न्यायाधीश रायपुर ओम प्रकाश साहू को चतुर्थ सिविल जज क्लास वन रायपुर, श्रम न्यायाधीश महासमुंद श्रुति दुबे को द्वितीय सिविल जज क्लास वन मुंगेली में पदस्थ किया गया है। श्रम न्यायाधीश दुर्ग यशोदा नाग को प्रथम सिविल जज क्लास वन एवं अतिरिक्त सीजेएम दुर्ग, श्रम न्यायाधीश कोरबा रूपनारायण पठारे को प्रथम सिविल जज एवं एडिशनल सीजेएम कोरबा के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं बेमेतरा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मती ममता पटेल को एफ टीसी जज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी संजय अग्रवाल को एफटीसी पाक्सो एक्ट बेमेतरा और प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर प्रबोध टोप्पो को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट मुंगेली में पदस्थ किया गया है।

पुलवामा के शहीदों को कोटि-कोटि नमन : भूपेश बघेल

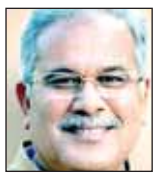

रायपुर (आरएनएस)। पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के वीर जवानों की शहादत को याद हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट के माध्यम से शहीदों को नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीटर एकाउंट में पोस्ट करते हुए लिखा- आज ही के दिन गत वर्ष पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को कोटि-कोटि नमन करता हूं। साथ ही लोकतंत्र का सिपाही होने के नाते पुनः सवालों को दोहराता हूं, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? हमले की जांच कहां तक पहुंची? शहीदों के परिवारों को न्याय मिल गया। ज्ञात हो कि गत वर्ष आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था।

नियमितीकरण एवं विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने दिया राज्यव्यापी धरना

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य के अनियिमित कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग, आउटसोर्सिंग से भरती बंद, 5 हजार दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण गृहनिर्माण मंडल, विद्युत मंडल, पर्यटन विकास निगम सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी विधानसभा के 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहे सत्र के मद्देनजर आज बूढ़ापारा धरनास्थल में प्रांतव्यापी धरना दिया गया। संघ के पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बताया कि पूर्व में अनेकों बार उक्त मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था।

विद्युत चोरी रोकने 28 हजार विद्युत कनेक्शनों की आकस्मिक जांच

» समुचित रौशनी संग सुरक्षित जीवन पाने ले विद्युत का वैध कनेक्शन-चेयरमेन श्री शुक्ला

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा प्रदेष के करीब 57 लाख विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने लेटेस्ट टेक्नालाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सस्ती बिजली की सहज उपलब्धता भी सुनिष्चित करने विषेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस दिषा में आगे बढ़ते हुये विद्युत चोरी, एवं दुरूपयोग को रोकने के लिये प्रदेषभर में आकस्मिक जॉच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कंपनी के सतर्कता विभाग की टीम ने प्रदेषभर में 28 हजार से अधिक विद्युत कनेक्षन की जॉच की। जिसमें 1720 विद्युत कनेक्षनों में बिजली चोरी का प्रकरण बनाया गया। ऐसे मामलों में लिप्त उपभोक्ताओं से 4 करोड़ 71 लाख रूपये की वसूली की गई। कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा जिला स्तर पर भी जॉच दल बनाये गये हैं। पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला एवं डिस्ट्रीब्टयूषन कंपनी के एमडी मोहम्मद केसर अब्दुल हक ने ग्रामीण एवं शहरी मैदानी अधिकारियों को विद्युत चोरी जॉच अभियान में तेजी लाने के निर्देष दिये।

राज्यपाल आज नागपुर और छिंदवाड़ा प्रवास पर जाएंगी

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज दोपहर बाद नागपुर और छिंदवाड़ा प्रवास के लिए रवाना होंगी। वे वहां 17 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राज्यपाल उइके अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज अपरान्ह 3 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी और शाम 4 बजे नागपुर पहुंचेंगी।

पारख ज्वेलर में हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाला शातिर चोर 36 घंटे बाद गिरफ्तार

» ऊंचे ख्वाब देखकर रचा था घटना को अंजाम देने का तरीका

» पूर्व में भी 13 चोरी के मामलों में हो चुका था गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर के हृदयस्थल आकाश गंगा सुपेला स्थित पारख ज्वेलर्स में हुए करोडो की चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी को पुलिस ने 36 घण्टो के बाद गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी चोरी के पैसों से शातिर चोर खोलना चाहता था आलीशान पार्लर खोलना चाहता था आरोपी मीनाक्षी पार्लर रायपुर से 06 माह का प्रषिक्षण प्राप्त किया है। वर्तमान में आरोपी गेलक्सी पार्लर, कबीरधाम का था संचालक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अभेद रणनीति से हुआ गिरफ्तार। छ.ग.राज्य में पहली बार चोरी की सम्पूर्ण जेवरात लगभग 03 करोड़ हुए जप्त। आरोपी लोकेश वास उर्फ गोलू है कवर्धा जिले का तड़ीपार। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी 13 चोरी के मामलों में हो चुका है गिरफ्तार। आरोपी 03 माह पूर्व ही रिहा हुआ था जेल से। चोरी करने के पूर्व पूरी रात आरोपी सोया रहा पारख ज्वेलर्स की छत पर। गिरफ्तार आरोपी लोकेश वास उर्फ गोलू पिता कपिल वास उम्र 29 वर्ष निवासी कैलाश नगर कवर्धा जप्तः- 03 करोड़ की सोने के जेवरात एवं एक लाख पचास हजार रूपये नगद 12 फरवरी 2020 को दुर्ग जिले के आकाश गंगा स्थित पारख ज्वेलर्स सुपेला में दीवाल तोड़कर तथा लॉकर काट कर करोडो के सोने के जेवरात चोरी की घटना घटित हुई थी।

चिटफंड कंपनियों के शिकार हुए पीड़ितों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

सुकमा (आरएनएस)। जिले में जागरूकता की कमी का फायदा चिटफंड कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर फरार हो गई है। पीड़ित अब थानों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे है। कार्रवाई के अभाव में अब पीड़ितों ने एसपी से मिलकर गुहार लगाई है। चिटफंड कंपनियो के फर्जीवाड़े में सुकमा में सबसे ज्यादा चिटफंड कपंनियों के शिकार कोंटा ब्लॉक से हैं। कई बार लोगों ने अपने स्तर पर पैसे मांगे लेकिन कपंनी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले में लगभग 04 से 05 करोड़ रूपये अलग-अलग चिटफंड कपंनी पैसे लेकर फरार हो गई है। कुछ पर कार्रवाई हुई, और कुछ अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मामले की शिकायत करने छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले करीब 30 लोग एसपी शलभ सिन्हा से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। साथ ही निवेशकों का पैसा वापस कराने का निवेदन किया गया है। एसपी सुकमा शलभ सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पदेन सदस्यों को नहीं मिला सुनवाई का अवसर

» 2004 के बाद बदल गया था आईएएस अधिकारियों का प्रभार

» सुप्रीम कोर्ट में यही रहा आधार

» मामला समाज कल्याण विभाग का

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निःशक्तजन घोटाला मामले पर सीबीआई जांच के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था। अब प्रकरण में नामित व्यक्तियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील के मद्देनजर प्रकरण पर स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संबंधित अधिकारियों को राहत मिल गई है। ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण के तहत एक हजार करोड़ रुपए के घोटाले किए जाने संबंधी याचिका दायर की गई थी, जबकि विभागीय तौर पर मात्र तेईस करोड़ रुपए ही स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा निःशक्तजन घोटाले में जिन अफसरों के नाम है, उन्हें विभागीय तौर पर नामित सदस्य के रुप में शामिल किया गया था। चूंकि वर्ष 2004 के बाद उन सभी का स्थानांतरण हो गया था।

बजट सत्र के लिए अब तक 18 सौ से अधिक प्रश्न लगे

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र के लिए अब तक 18 सौ से अधिक प्रश्न लग चुके है। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है जो 01 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। इन बैठकों के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बढ़-चढ़कर प्रश्न लगाए जा रहे है। 13 फरवरी तक की स्थिति में 1802 प्रश्न सदस्यों द्वारा लगाए जा चुके है।

» किसानों को 13 हजार 609 करोड़ रूपए का भुगतान

समर्थन मूल्य पर अब तक 17.61 लाख किसानों से 78.29 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश में अब तक 17 लाख 61 हजार किसानों से 78 लाख 29 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 लाख अधिक किसानों से धान बिक्री की गई। धान बेचने वाले किसानों को 13 हजार 609 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्ज माफी से लाभान्वित किसानों को इस वर्ष सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए पहली बार अवसर मिला है। पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 15 लाख 71 हजार किसानों द्वारा धान बिक्री की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनवरी 2020 तक राज्य का 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन उसना चावल सेन्ट्रल पूल में और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जनवरी 2020 तक 12 लाख 78 हजार मीट्रिक टन अरवा चावल राज्य के पूल में लिया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के किसानों को धान विक्रय का पूरा लाभ मिले, इसके लिए राज्य के बाहर से आने वाले अवैध धान

तथा प्रदेश के भीतर अवैध रिसाईकलिंग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है। अब तक अवैध धान परिवहन के 4 हजार 482 प्रकरण दर्ज कर 46 हजार 194 टन अवैध धान जब्त किया गया। धान परिवहन करने वाले 441 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है। पूर्व में धान खरीदी की अवधि 15 फरवरी 2020 निर्धारित था।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्थक हेतु नंबर 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को इसके कार्यक्रमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में तथ्य किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित शिक्षा कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल निवासी एवं महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU